

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.824  
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का क्रियान्वयन

+824. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में पीएम ई-बस सेवा योजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत मैंगलोर को स्वीकृत सौ इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार को चार्जिंग डिपो, पार्किंग सुविधाओं या संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए भूमि चिह्नित करने के संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार या मैंगलोर नगर निगम से कोई पत्राचार या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) इस योजना को समय पर शुरू करने के लिए राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय को आगे क्या कदम उठाने होंगे; और
- (ङ) सरकार द्वारा शहरों के लिए भूमि आवंटन, एसपीवी व्यवस्था, निविदा और बसों को चलाने जैसी प्रारंभिक कार्रवाई पूरी करने के लिए क्या समय-सीमा और शर्तें निर्धारित की गई हैं?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू)

(क): 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई "पीएम-ई-बस सेवा" योजना का उद्देश्य पीपीपी मॉडल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ाना है।

योजना की प्रगति:

बस की मांग

मंत्रालय ने 15 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों की 9,360 ई-बसों की मांग को अनुमोदित कर दिया है। ये अनुमोदित बसें योजना के दिशानिर्देशों और परिशिष्ट (15 अप्रैल 2025) के अनुसार

स्वीकृत की गई हैं और 106 शहरों में उपलब्ध हैं। राज्य-वार स्वीकृत बसों की जानकारी अनुलग्नक-1 में दी गई है।

### **संबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर [बस डीपो और बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर]**

- अब तक बीटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत परियोजनाएं: **88**
- अब तक सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत परियोजनाएँ: **85**
- अब तक संबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल स्वीकृत राशि: **1,075.31** करोड़ रुपये

### **बस निविदा प्रगति**

- अब तक निविदा में शामिल बसें: **6,518**
- अब तक जारी मात्रा पुष्टि पत्र (एलओसीक्यू): **5,918**
- अब तक जारी अवार्ड लेटर: **4,447**

(ख) से (ड): कर्नाटक राज्य के लिए कुल 750 ई-बसों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें मेंगलोर के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इन बसों की निविदा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा बेहतर मूल्य निर्धारण हेतु मांग को एकत्रित करके की जाती है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने मेंगलोर शहर के मुदुपी और कुंतिकाना के प्रत्येक इलाके में 50 ई-बसों को समायोजित करने की क्षमता वाले डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

पीएम-ई-बस सेवा योजना को समय पर लागू करने के लिए, शहरों/शहरी स्थानीय निकायों को बस संचालन शुरू होने से पहले कार्यान्वयन-पूर्व गतिविधियाँ पूरी करनी होती हैं, जैसे डिपो के लिए भूमि आबंटन, सिविल और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए निविदाओं की प्रक्रिया, डिपो के लिए कार्य, संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और विशेष प्रयोजन तंत्र व्यवस्था। कार्यान्वयन-पूर्व गतिविधियों को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, योजना में अधिकतम 10 वर्षों या मार्च 2037 तक, जो भी पहले हो, के लिए सब्सिडी का प्रावधान है।

\*\*\*

पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य-वार स्वीकृत ई-बसों की सूची

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	शहरों की संख्या	स्वीकृत बसें
1	असम	01	100
2	आंध्र प्रदेश	11	1050
3	बिहार	06	400
4	छत्तीसगढ़	04	240
5	गुजरात	08	780
6	हरियाणा	07	450
7	मध्य प्रदेश	08	972
8	महाराष्ट्र	22	1559
9	मेघालय	01	55
10	ओडिशा	05	400
11	पंजाब	05	447
12	राजस्थान	09	1150
13	उत्तराखण्ड	02	138
14	कर्नाटक	10	750
15	चंडीगढ़ (यूटी)	01	428
16	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	02	200
17	लद्दाख (यूटी)	01	15
18	पुदुचेरी (यूटी)	01	75
19	तेलंगाना	02	151
	कुल	106	9360